

- महर्षि आयुर्वेद कारपोरेशन
- उल्टा - पुल्टा
- झन्डे का कमाल
- झलानी टूल्स
- आटोपिन
- फतवे

प्रदर्शनों की भाप

सत्ता पिघल गई

मार्च के आरम्भ में फ्रांस सरकार ने एक योजना की घोषणा की। इसके मुताबिक मैनेजमेंटें 25 वर्ष से कम आयु के वरकरों को इस समय जो कानूनन न्यूनतम वेतन है उससे 20 से 70 प्रतिशत तक कम वेतन पर रख सकती हैं। सरकारी स्कीम के खिलाफ फ्रांस के कोने-कोने में जलूसों का सिलसिला आरम्भ हो गया। छात्रों के जलूसों में उनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी शामिल हुये। छात्रों और मजदूरों ने सौंझे जलूस निकाले। पुलिस से टकराव हुये - ऑसू गैस के गोलों और गिरफ्तारियों का दौर चला। रेल व रोड़ जाम किये गये। 1968 में छात्र-मजदूर विरोध पेरिस में सीमित था जबकि मार्च 94 के विरोध प्रदर्शनों की लहर फ्रांस-व्यापी रही।

12 मार्च को पेरिस में 50 हजार का जलूस। 16 मार्च को विभिन्न शहरों-कस्बों में 2 लाख लोग विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुये।

18 मार्च को पेरिस, बास्तिया और कोर्सिका में पुलिस से टकराव तथा गिरफ्तारियाँ। 25 मार्च के प्रदर्शनों में एक लाख लोग। पेरिस में 30 हजार के जलूस को कन्दोल करने के लिये 3,300 पुलिस वाले। ल्यों नगर में 30 हजार के जलूस ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिये 2 अल्जीरियाइयों के फ्रांस-निकाले के सरकारी हुकम के खिलाफ रोष-प्रकट किया।

विरोध लहर के बढ़ते जाने पर शासकों को 1968 के पेरिस छात्र-मजदूर उभार का भूत डराने लगा और फ्रांस सरकार ने अपने अटल फैसले को एक महीने की टक्कर के बाद टाल दिया। एयर फ्रांस के मजदूरों ने तीखा संघर्ष करके सरकार को 4 हजार वरकरों की लाजमी छँटनी की स्कीम को छोड़ने को मजबूर किया था। उसी प्रधानमन्त्री के एक और अटल फैसले को लोगों के सामुहिक कदमों ने फिर मोम की तरह पिघला दिया है।

फलता-फूलता उद्योग!

अमरीका में कैलिफोर्निया प्रान्त की विधानसभा ने 1977 के वाद सजा बढ़ाने व नये अपराधों की सृष्टि करने वाले एक हजार कानून बनाये हैं। जेलों के निर्माण पर अधिक व्यय करके कैलिफोर्निया के विधायकों ने जेल निर्माण में विश्व में अव्वल स्थान हासिल कर गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है।

1980 में जेलों पर वार्षिक व्यय के लिये कैलिफोर्निया की प्रान्तीय सरकार ने 900 करोड़ रुपये निर्धारित किये थे। 1995 के बजट में यह रकम 9 हजार करोड़ रुपये हो जायेगी। दस वर्षों से जेलों के बजट की वृद्धि-दर स्कूलों के लिये बजट की वृद्धि-दर से तीन गुणा ज्यादा है। 1977 में कैलिफोर्निया में 19,623 कैदी थे जो 460 प्रतिशत वृद्धि के बाद 1992 में एक लाख दस हजार हो गये। जेलें इस प्रान्त में अधिकतम वृद्धि वाला उद्योग है - 1983 के बाद प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन बिल में नये जेल गार्डों की भर्ती से हुई वृद्धि अन्य सब सरकारी विभागों

में नई भर्तियों से हुई वृद्धि के जोड़ के बराबर है।

आज कैलिफोर्निया में जेलों का ताना-वाना 1937 में हिटलर के समय जर्मनी में जेलों के जाल से भी बड़ा है। और राज्यपाल ने 7 मार्च 94 को एक नये कानून पर दस्तखत किये हैं जिससे मौजूदा 28 जेलों में 6 वर्षों में 20 जेलों की वृद्धि होगी। बढ़ते असन्तोष व संघर्षों से बौखलाये शातिर लोगों की यह बेवकूफी शासक वर्ग के दिवालियेपन का एक लक्षण मात्र है।

1990 में कैलिफोर्निया में वोटर्स ने सरकार द्वारा नई जेलें बनाने के लिये 1350 करोड़ रुपये की एक बान्ड योजना को ठुकरा दिया था। अब प्रान्तीय सरकार ने पैसे उगाहने के लिये ऐसी योजना अपनाई है जिसके लिये मतदाताओं की राय लेने की संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। बेशक, इस तरीके के लिये सरकार को कुछ ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। बजट घाटा बढ़ेगा। टैक्स बढ़ाने होंगे। यह असंतोष व संघर्षों को और बढ़ावेंगे!

कैदी के उद्गार

(नीचे हम एक कैदी स्टीफन विन्डसर के पत्र के अंशों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं।)

कोई भी अपराध क्यों न किया हो, जेल में होना किसी के भी लिये कठिन जीवन है।

मेरी तरह कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको जेल में रखना उसके आत्मबल पर हमला करना है। जैसी पोजीशन में मैं अपने को पाता हूँ ऐसे में एकमात्र बनेफिट यह है कि उन संघर्षों, जिन्हें करना उसकी मजबूरी है, उनसे कैदी बहुत बल प्राप्त करता है।

जो लोग दी गई सजा के खिलाफ जेल से संघर्ष जारी रखते हैं वे कभी-न-कभी काल-कोटरी में बन्द कर दिये जाते हैं।

सोलिड 14 महीने में एक ऐसे कमरे में बन्द रखा गया जो पेशाबघर जितना था - 14 महीनों के लिये अपने गुसलखाने में बैठे रहने की कल्पना कीजिये।

सम्पर्क के किसी स्रोत का होना कैदी के लिये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पत्र अत्यावश्यक हैं और जितने अधिक हों उतना ही अच्छा लगता है। किसी अजनबी का ही क्यों न हो, आप उस भावना की कल्पना नहीं कर सकते जो पत्र मिलने पर होती है।

कैदी कम ही माँग करते हैं। वे उन पर कोई बात नहीं थोपते जो उन्हें खत लिखते हैं। जब-तब अजनबियों से मिलने वाले पत्रों ने मेरे होशो-हवास को बरकरार रखा है और मुझे उन दौरों में जिन्दा रखा जब मैं चौड़े होते गड्डे में धँसता जा रहा था। निकलने का कोई रास्ता नहीं, बस वारडरों द्वारा पहुँचाई जाती अनन्त मानसिक यातना। मार-पीट झेलने को कैदी मजबूर होता है।

उन 14 महीनों के दौरान दो कैदी खुद को फाँसी लगा कर मर गये। और हर हफ्ते कम से कम एक आत्महत्या की कोशिश होती थी तथा ऐसा करते समय कैदी स्वयं के शरीर को गम्भीर नुकसान पहुँचाते थे।

कैदी अक्सर अपने परिवार को वह नहीं बता सकता जो जेल में हो रहा होता है पर जब-तब लिखने वाले अजनबी को अपने उद्गार प्रकट कर सकता है।

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस बारे में लिख रहा है। मेरे पास सदा ही उत्तर देने के लिये समय होता है। और विश्वास करें या नहीं, मुझे जब लगता है कि मैं दे सकता हूँ, तब मैं सलाह भी देता हूँ।

यह जानकारी कि किसी ने लिखने का कष्ट किया है उस समय आशा का संचार करती है जब चार दीवारों के सिवा और कुछ नहीं होता।

Stephen Windsor, HMP
Noranside, Fern-by-Forfar,
Scotland, Britain

मजदूरों द्वारा अपने अनुभवों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिये लिखे लेखों और रिपोर्टों को हम इस पन्ने पर छापेंगे। ऐसे लेख और रिपोर्ट हमारे लिये खुशी की चीज हैं। अपनी बात हमें लिख कर दें। आपको अपनी बातें छपवाने के लिये कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे।

महर्षि आयुर्वेद कारपोरेशन

आगे समाचार यह है कि हम महर्षि आयुर्वेद कारपोरेशन लिमिटेड के सभी कर्मचारी कम्पनी के मैनेजमेंट से लगभग सात साल से भारी दुःखों का सामना करते आ रहे हैं। श्रमिकों से जबरन सादे कागज सादे वोचर में हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। उनकी बातों को यदि श्रमिक नहीं मानते हैं तो श्रमिकों के साथ घोर अन्याय करते हैं जैसे कि मार-पीट करना, जबरदस्ती काम करवाना, समय से वेतन नहीं देना, प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम लेना। इन समस्याओं से तंग आकर हमने एक यूनियन का संगठन किया। हम सभी श्रमिकों ने एक मामूली डिमान्ड-नोटिस मैनेजमेंट को दिया। फिर भी मैनेजमेंट ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जबकि शोषण की गति और आगे की ओर बढ़ा दी। हम लोगों ने 08.11.93 को वही डिमान्ड नोटिस श्रम समझौता अधिकारी फरीदाबाद को दिया। उस पर लगभग दस तारीखों में बहस हुई। उसके बाद 11.01.94 को श्रम समझौता अधिकारी के समक्ष हमारी डिमान्ड नोटिस का फैसला हो गया। दिनांक 08.11.93 से लेकर 11.01.94 के बीच मैनेजमेंट ने जबरन 40-45 श्रमिकों का हिसाब अवैध रूप से दे दिया जो कि महर्षि जैसे लोगों के लिये घोर निन्दनीय है।

श्रम समझौता अधिकारों के समक्ष ये समझौता हुआ कि जिस श्रमिक की सेवा अवधि 240 दिन पूर्ण हो चुकी है उसके मासिक वेतन में एलाउन्स के रूप में बीस परसेन्ट की बढ़ोतरी की जायेगी जो कि कमरे का एलाउन्स, कनवेयन्स, एल टी ए इत्यादि होगी। साल में दो जोड़ी यूनiform, प्रतिमाह एक किलो कपड़े धोने का साबुन, एक साबुन हाथ धुलाई करने का, जूता, चप्पल इत्यादि 31 मार्च 1994 तक सभी श्रमिकों को मिल जाने चाहियें थे। लेकिन समझौता पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। श्रमिकों को समझौता के बाद भी मासिक वेतन न दे कर के दिहाड़ी वेतन दिया जाता है। साप्ताहिक छुट्टी एवं सभी छुट्टी में रूपया काट लिया जाता है। समझौता में प्रबन्धक प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया था कि किसी भी यूनियन के कर्मचारी के साथ बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। कम्पनी ने लगभग साठ लोगों को सैक्टर-39 नोयडा (महर्षि नगर) में रहने की व्यवस्था की है। सुबह 7 बजे स्टाफ बस महर्षि आयुर्वेद कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद ले कर आती है; शाम 5 बजे स्टाफ बस पुनः महर्षि नगर नोयडा ले जाती है जो कि बन्धुआ मजदूर साबित करता है।

कम्पनी की मैनेजमेंट ने बदले की भावना को कायम रखते हुये यूनियन के पदाधिकारी, प्रधान अवनीश कुमार तिवारी तथा महासचिव श्री दिनेश कुमार दीक्षित, बड़े भाई एवं पिता, वैद्य आई के तिवारी व वैद्य कृष्ण कुमार दीक्षित को दिनांक 13.04.94 को रात्रि करीब 1 बजे सैक्टर-39 महर्षि नगर नोयडा गाजियाबाद थाना की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा के गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद वैद्य आई के तिवारी एवं वैद्य कृष्ण कुमार दीक्षित को मेरठ जेल की रोटी खानी पड़ी।

अजिबो-गरीब बात यह कि प्रधान अवनीश कुमार तिवारी एवं महासचिव दिनेश कुमार दीक्षित को मैनेजर ने दिनांक 14.04.94 को बुलाकर अनेकों प्रकार की धमकी दी तथा प्रलोभन भी दिया कि तुम लोग अपनी सर्विस से रिजाइन दे दो। मगर उनकी बातों में ये लोग नहीं आये तो दिनांक 15.04.94 को अवनीश कुमार तिवारी, दिनेश कुमार दीक्षित, रामउदगार दास, अविनाश झा, सुभाष मिश्रा, हरे राम को इयूटी से रोक दिया गया। सब यूनियन के कर्मचारियों ने ये माँग की कि हमारे लीडर को अन्दर आने दिया जाये। लेकिन कम्पनी की मैनेजमेंट ने गुण्डों की सहायता से 80-85 श्रमिकों को कार्ड पंच करने के बावजूद भी गेट से बाहर निकाल दिया।

दिनांक 16.04.94 को सूरज कुण्ड थाना प्रभारी की सहायता से 6 कर्मचारियों के अलावा बाकी कर्मचारियों को इयूटी में ले लिया गया। बाकी 6 कर्मचारी यूनियन के सक्रिय सदस्य हैं एवं पदाधिकारी फरीदाबाद के रोड़ पर, कोर्ट के दरवाजे पर गुहार मार रहे हैं। फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उपरोक्त ऊपर लिखी गई बातों पर भारत सरकार से हम महर्षि आयुर्वेद के श्रमिक सच्चे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कही-सुनी-देखी

★ **दुनियाँ में जगह-जगह यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि सबके लिये खाना और पानी तो फ्री होना ही चाहिये।**

★ **हितकारी पोर्ट्रीज के गेट पर 16 अप्रैल को इन्टक का एक बड़ा लीडर स्कूटर स्टार्ट कर रहा था जब वहाँ से निकल रहे तीन वरकर उससे बात करने लगे।**

वरकर : “नेताजी, आपने एग्रीमेन्ट में यह भी समझौता किया है क्या कि तनखा 7 तक देने की वजाय 16 तक भी नहीं दी जाये?”

लीडर : “नहीं भाईसाहब ऐसी तो कोई बात नहीं है।”

वरकर : “तो फिर, क्या बात है कि मैनेजमेन्ट 16 से पहले कभी तनखा नहीं देती और आप कुछ नहीं करते।”

लीडर : “आपको टाइम पर तनखा नहीं मिलती यह बात मुझे आज तक तो किसी वरकर ने नहीं बताई।”

वरकर : “आप तीन साल से हर महीने आ कर मन्थली ले जाते हैं क्या आपको पता नहीं कि तनखा टाइम पर नहीं दी जाती?”

लीडर : “अच्छा मैं परसों आऊँगा और तब मैनेजमेन्ट और तुमसे बात करूँगा।”

★ **“ईश्वर-अल्लाह की निन्दा और सब पुस्तकों, धार्मिक हों चाहे अन्य कोई, की आलोचना के मनुष्य के अधिकार पर मैं अटल हूँ।” - 27 अप्रैल के पायनियर में दिलीप सिमियन।**

★ **दिल्ली में कोठियों में काम करने वाले वरकरों की एक मीटिंग में एक पोस्टर पर लिखा था : “हमारे काम में तीन समस्याएँ हैं : (1) कम रुपयों में अधिक काम, (2) अमानवीय व्यवहार, (3) दोषारोपण।”**

★ **वैशाली एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले झालानी टूल्स के मजदूरों से सुना : “वैशाली एक्सप्रेस रात को सात चालीस पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। इस गाड़ी में दो जनरल डिब्बे होते हैं और उनमें बैठने के लिये लोग सुबह छह-सात बजे से ही प्लेटफार्म पर लाइन में लगने लगते हैं। बारह घन्टे तक सामान के साथ प्लेटफार्म पर लोगों की लम्बी लाइन लगी रहती है। यह साल के 365 दिन होता है। और बारह घन्टे की लाइन के बाद डिब्बे में खड़े हो कर जाने के लिये भी धक्का-मुक्की होती है। कार्तिक और चैत की छठ तथा ब्याह-शादी के मौकों पर लाइन प्लेटफार्म के छोर से मुड़ कर वापस शुरू की जगह पहुँच जाती है। इन मौकों पर पुलिस चाँदी कूटती है। लाइन तुड़वा कर पुलिस लाठियाँ बरसाती है और पैसे ले कर लोगों को डिब्बों में घुसाती है। कई बार 12-14 घन्टे लाइन में लगने के बाद ऐसे मौकों पर हमें वापस फरीदाबाद आना पड़ता है।”**

★ **एक फैक्ट्री में एक वरकर की इनक्वायरी चल रही थी। इनक्वायरी अफसर, कम्पनी का परसनल मैनेजर, जिस वरकर की इनक्वायरी चल रही थी वह और उसका एक गवाह उपस्थित थे। गवाही दे रहा मजदूर अटक-अटक कर बोल रहा था और इनक्वायरी अफसर उसे बार-बार टोक रहा था। इस पर जिस वरकर की इनक्वायरी चल रही थी वह बोला, “वकील साहब आप रोज अदालत में पेश हो कर झूठ बोलने में पी एच डी हो गये हो, हमारा परसनल मैनेजर भी झूठ बोलने में पी एच डी है और इधर इनक्वायरी की मीटिंगों में बैठ कर मैं भी झूठ बोलने में पी एच डी हो गया हूँ। मेरे गवाह इस मजदूर की अभी प्रेक्टिस नहीं हुई है इसलिये इसे थोड़ा आराम से बोलने दो ताकि यह भी जल्दी ही झूठ बोलने में पी एच डी हो जाये।”**

★ **हिन्दुस्तान वायर का एक वरकर लखानी फुटवियर के दस साल पुराने वरकर की पंखा खरीदने की क्षमता नहीं होने का समाचार पढ़ कर हँसने लग। फिर उसने कहा, “मुझे हिन्दुस्तान वायर में काम करते 6-7 साल हो गये थे। नाइट डिप्टी करके गर्मियों में एक दिन मैं सो रहा था। एक-डेढ़ बजे मिलने आये एक रिश्तेदार ने मुझे उठाया। मुझे पसीने में तर देख कर वे बहुत नाराज हुये और कहने लगे कि नौकरी करने का फायदा ही क्या जब पैंखा तक नहीं खरीद सकते। मैं चुप रहा, बोल ही क्या सकता था। रेलवे में नौकरी कर रहे उस रिश्तेदार ने तब मुझे पैंखा दिया और वही मैं अब भी इस्तेमाल कर रहा हूँ।” उसी समय वहाँ बैठा वर्कशॉप का एक वरकर बोल उठा, “पैंखा खरीदने की तो मैंने कभी सोची ही नहीं है क्योंकि अपने बस की बात नहीं है। रेडियो खरीदने की मेरी चाह बहुत दिनों से है पर वर्कशॉप में छह साल काम करके भी मैं रेडियो नहीं खरीद पाया हूँ।”**

इस अखबार को हम अधिक संख्या में छापना चाहते हैं ताकि बड़ी तादाद में मजदूर इसे पढ़ें और यह अखबार भी अनुभवों तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक मंच बने। रुपये-पैसे की कमी हमारे लिये एक बाधा है। अगर आप इस अखबार को उपयोगी समझते हैं तो कृपया आर्थिक योगदान भी दें।

उल्टा-पुल्टा

नागपुर महानगर है। भारत सरकार ने कभी भीख माँगने पर रोक लगाने का एक कानून बनाया था। भिखारियों को रखने के लिये नागपुर महानगरपालिका भवन में भिक्षा निवारण केन्द्र स्थापित किया गया। कोई भिखारी नहीं होने की वजह से छह साल से इस भिक्षा निवारण केन्द्र पर ताला पड़ा है।

नागपुर के पूर्व राजा तेज सिंह राव भोंसले के राजमहल के बगल में हुजुरपागा नामक अस्तबल में कभी भोंसले खानदान के घोड़े बन्धते थे। तेज सिंह राव भोंसले अब एम पी है और उसकी पत्नी चित्रलेखा के नाम हुजुरपागा घुड़साल है। 1984 में सरकार ने यह अस्तबल 6,075 रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया ताकि इसमें भिखारियों

को रख कर भीख पर रोक के कानून पर अमल हो सके। 1987 में किराया 9,785 रुपये कर दिया गया। फिर 1989 में किराया बढ़ा कर 19,335 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके बाद किराया 1993 में बढ़ाया गया पर लागू 1991 से किया गया और यह तीस हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

कुछ माह पहले नागपुर के पूर्व राजा की पूर्व घुड़साल में 6 भिखारी थे और उनकी देखभाल के नाम पर 17 अधिकारी थे। आजकल सामान्यतः 23-24 भिखारी यहाँ रखे जा रहे हैं और इन्हें भागने से रोकने के लिये इन पर 22 सरकारी अधिकारी तैनात हैं जिनका वेतन 70 हजार रुपये प्रतिमाह है।

भूख हड़ताल भरपेट भोजन के लिये

आई टी कालेज लखनऊ के होस्टल की छात्राओं ने कम और खराब खाने के विरोध में 21 अप्रैल को भूख हड़ताल कर दी। मैनेजमेन्ट को बार-बार शिकायत करने पर भी स्थिति में सुधार नहीं किये जाने पर लड़कियों ने यह कदम उठाया था। भूख हड़ताल आरम्भ करते ही छात्राओं ने नारों के संग-संग पूरे कालेज में तीखे-भावपूर्ण

पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिये। भूख हड़तालियों ने चार सूत्री माँग-पत्र पेश किया था जिसमें प्रमुख माँग भरपेट खाना दिये जाने की थी। कालेज प्रशासन को मामला कन्ट्रोल से बाहर जाता लगा। तब 22 अप्रैल को मैनेजमेन्ट ने छात्राओं की डिमाण्डें मानी।

शक्ति-भक्ति और शक्ति-प्रदर्शन की नकेल : सामुहिक कदम

25 वर्षीय मनोरमा की 28 मार्च को मृत्यु हो गई। एक वकील के घर सफाई करते समय कूलर से करन्ट लगने को मौत का कारण बताया गया। वकील परिवार के सदस्यों को अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

पोस्ट मार्टम में बलात्कार के बाद हत्या का मामला सामने आया। इस पर पुलिस ने मनोरमा के पति की डाक्टरी जाँच के लिये उसे आठ घन्टे थाने में बैठा कर रखा। साधन-सम्पन्न लोगों के घरों में बर्तन माँजने, झाड़ू-पोंछा का काम करने वाली मनोरमा का पति रिवक्शा चलाता है।

नागपुर, जहाँ यह घटना घटी, वहाँ के लोगों का इस शक्ति-भक्ति और शक्ति-प्रदर्शन के

खिलाफ सामुहिक आक्रोश फूट पड़ा। 2 अप्रैल को उत्तरी नागपुर बन्द के दौरान गुस्से से फुँफकारती भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वकील की कोठी की सुरक्षा के लिये मोर्चाबन्दी की। 3 अप्रैल को कोठियों में काम करने वाले वरकरों ने नागपुर में हड़ताल की।

लोगों के सामुहिक आक्रोश ने, सामुहिक कदमों ने शक्ति-भक्ति और शक्ति-प्रदर्शन के नकेल डाली। अदालत को वकील परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करनी पड़ी और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा तथा सरकार को घटनाक्रम की सी आई डी जाँच का आदेश देना पड़ा है।

फतवे

तीस साल हो गये हैं सादिक हुसैन को मरे हुये। उसकी किताब 'तारीख-ए-मुजाहिदीन' को आखिरी बार छपे बीस साल से ऊपर हो गये हैं।

हाल ही में पंजाबी अखबार अजीत ने पहले पन्ने पर सुर्खियों में खबर छपी : सादिक हुसैन ने अपनी किताब 'तारीख-ए-मुजाहिदीन' में सिख गुरुओं का अपमान किया है। इस खबर से पहले पंजाब या भारत में इस बारे में शायद ही किसी को कोई जानकारी हो। लेकिन शीघ्र ही भर्त्सना-धमकी भरे बयानों की झड़ी लग गई।

पंजाब युवा काँग्रेस के प्रधान ने ऐलान किया कि किताब के लेखक का सिर काट कर जो लायेगा उसे एक करोड़ रुपये इनाम में दिये जायेंगे। फिर सिख लोअर कोर्ट नाम के संगठन की तरफ से भी एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की गई। पंजाब और हरियाणा विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से किताब पर पाबन्दी के लिये प्रस्ताव पास किये। जलसे-जलूस-प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। यह सब करने वालों में शायद ही किसी ने किताब देखी थी।

समाचार सार

★ फौज में भर्ती होने से इनकार करने के लिये स्पेन में 115 लोग जेल में बन्द हैं। एक हजार लोगों ने राजधानी मैड्रिड में इन कैदियों के समर्थन में जलूस निकाला और इनकी रिहाई डिमांड की।

★ कनाडा के प्रधानमंत्री के 18 मार्च को प्रथम गृह आगमन को मनाने के लिये एक संवाददाता सम्मेलन भी रखा गया था। प्रधानमंत्री प्रेस से गप-शप कर रहे थे कि 300 बेरोजगार कन्स्ट्रक्शन वरकर शीशे का दरवाजा तोड़ कर कमरे में घुस आये। वे नारे लगा रहे थे, "प्रधानमंत्री झूठा है!" कनाडा पुलिस घबराये हुये प्रधानमंत्री को मजदूरों के गुस्से से बचा कर ले गई। आक्रोश-भरे स्वर में मजदूरों ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान नौकरियाँ देने का आश्वासन देने वाले इस आदमी ने नौकरी तो क्या देनी थी, प्रधानमंत्री बनते ही इसने बेरोजगारी भत्ते में कटौती कर दी है।

★ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी - बहुजन समाज पार्टी मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल को नगरपालिकाओं के वरकरों द्वारा हड़ताल करने पर 6 महीनों के लिये पाबन्दी लगा दी।

★ मृत्यु की भविष्यवाणी एक अच्छ-खासा धन्धा है। मौत के मुहाने पहुँचे मरीजों से उनकी जीवन बीमा पालिसियाँ पालिसी का आधे से तीन-चौथाई पैसा भुगतान करके खरीदना अच्छे मुनाफे का धन्धा है। अमरीका में टेक्सास प्रान्त की विधानसभा के सदस्य चिजम के अनुसार इसमें 17 से 27 प्रतिशत की दर का मुनाफा है। एड्स के शिकार 6 लोगों की जीवन बीमा पालिसियाँ 70 लाख रुपये में खरीदने वाला विधायक चिजम कहता है कि यह लोग एक महीने के अन्दर मर गये तो उसे छप्पर फाड़ मुनाफा होगा!

★ एक तम्बाकू कम्पनी के वैज्ञानिकों की रिसर्च ने 1983 में यह साबित किया कि तम्बाकू में होने वाली निकोटिन आदत डालने वाला नशा है। यह रिसर्च एक साइन्स पत्रिका में छपने को ही थी कि मैनेजमेन्ट ने वैज्ञानिकों को अपना लेख वापस माँगने को मजबूर किया। अब साइन्स क्षेत्रों में यह आम मान्यता है कि लेख को प्रकाशन से वापस लेने की वजह से तम्बाकू पर रिसर्च छह साल पीछे धकेल दी गई।

★ सरकारी आँकड़ों के मुताबिक अमरीका में फुल-टाइम काम करने वाले वरकरों में से भी 18 प्रतिशत वरकर अपने को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकते। युवा वरकरों में यह हालात तेजी से बढ़ रहे हैं। 1979 में 18 से 24 वर्ष के बीच आयु के फुल-टाइम वरकरों में से 23 प्रतिशत वरकर जहाँ इस पोजीशन में थे वहाँ 1992 में ऐसे 47 प्रतिशत फुल-टाइम वरकर गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिये गये थे।

झन्डे का कमाल

13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित दवाई फैक्ट्री ब्रॉन लेवोरेट्रीज में प्रोडक्शन शुरू हुये दो साल हो गये हैं। अपनी ओखला फैक्ट्री से यहाँ शिफ्ट किये कुछ वरकरों के अलावा अन्य किसी मजदूर को मैनेजमेंट ने परमानेन्ट नहीं किया है। ब्रेक और नई भर्ती का एक अटूट सिलसिला जारी है। जनवरी में 15 वरकर निकाले गये। फरवरी में 44 को निकाल कर उनमें से 27 की नई भर्ती की गई।

वरकर संगठित हुये। अपनी ताकत को और बढ़ाने की सोच कर यह झन्डे वालों के पास गये। 17 फरवरी को एक झन्डा फैक्ट्री गेट पर फहराने लगा।

मैनेजमेंट ने 5 मार्च को 11 वरकरों का गेट रोक दिया। झन्डे वालों के आदेश पर वरकरों ने इसके खिलाफ टूल डाउन किया। 6 को भी टूल डाउन। 7 मार्च को शर्तों पर दस्तखत के बाद प्रवेश की इजाजत। झन्डे वालों ने मजदूरों को साइन करने से मना कर दिया। फरवरी की ननखा विना वरकर गेट बाहर कर दिये गये। मैनेजमेंट और झन्डे की मिली भगत का यह खुला सबूत था पर ब्रॉन वरकरों को दिखाई नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अन्य मजदूरों के अनुभवों को जानने की कोशिश नहीं की।

जोश में भरे युवा वरकर धरने पर बैठ गये। लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिये हर रोज सुबह-शाम जलूस निकालने, अपने हालात से अन्य मजदूरों को परिचित कराने के लिये जगह-जगह पोस्टर चिपकाने, टीमें बना कर अन्य फैक्ट्रियों के वरकरों से सम्पर्क का सिलसिला शुरू करने जैसे कदम ब्रॉन वरकरों ने भी नहीं उठाये।

पूछने पर वरकर भरोसे से कहते कि पटना सम्मेलन से लौटते ही झन्डे वाले 21 मार्च को मामला हल कर देंगे।

पटना से लौट कर लेबर डिपार्टमेंट में 6-7 तारीखों के बाद 6 अप्रैल को झन्डे वालों ने कहा कि मैनेजमेंट हाई कोर्ट से आदेश ले आई है और वरकरों ने फौरन काम शुरू नहीं किया तो वह नई भर्ती कर लेगी। 7 अप्रैल को मजदूरों ने मैनेजमेंट की शर्तों पर काम शुरू कर दिया।

और, 16 अप्रैल को ब्रॉन लेवोरेट्रीज के वरकरों ने फैक्ट्री गेट पर टेंगे लाल झन्डे को उतार कर उसकी जगह हरा झन्डा टाँग दिया।

झालानी टूल्स

फरीदाबाद स्थित तीन प्लान्टों में छँटनी के बाद स्टाफ में 400 लोग हैं। इन्हें विना वेतन काम करते तीन-तीन महीने हो जाते हैं।

परेशान स्टाफ का आक्रोश कई बार फूटा है। पहले-पहल स्टाफ में भी लीडर उभरे पर कुचल दिये जाने अथवा मैनेजमेंट से मिल जाने, दोनों मामलों में स्टाफ को नुकसान ने झालानी स्टाफ में लीडर-विरोधी व्यापक भावना को जन्म दिया है। इससे इनमें सबकी पहलकदमी में सामुहिक कदम उठाने की प्रवृत्ति बढी है।

फरवरी वेतन का भुगतान 12 अप्रैल से पहले कर देने का मैनेजमेंट का आश्वासन फिर धोधा साबित हुआ। इस पर फस्ट

प्लान्ट का स्टाफ फैक्ट्री के अन्दर एक जगह धरने पर बैठने लगा और वरकरों ने स्टाफ का हौसला बढ़ाया। जब यह पता चला कि स्टाफ के ही कुछ लोग मैनेजमेंट से बात करने गये हैं तो उन्हें खूब झाड़ लगाई गई। पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे स्टाफ के लोगों ने कहा, “स्टाफ की तरफ से मैनेजमेंट से बात करने कोई नहीं जायेगा। मैनेजमेंट ने बात करनी है तो यहाँ आ कर सबसे बात करे।”

मैनेजमेंट बात करने तो नहीं आई पर स्टाफ की दो दिन की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद चुपचाप फरवरी का वेतन दे दिया गया।

आटोपिन

वैन्डिंग सैक्शन में मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित 500 पीस का प्रोडक्शन देना काफी भारी काम था। इसलिये यहाँ के वरकर ट्रान्सफर के चक्कर में रहते थे।

फिर भी, मैनेजमेंट ने एक इनक्रीमेंट के बदले जब प्रोडक्शन 625 पीस निर्धारित किया तब वरकर यह प्रोडक्शन देने लगे। एक और इनक्रीमेंट के बदले 750 पीस का प्रोडक्शन वरकर देने लगे।

जब-तब वहाँ लगाये जाते एक जनरल आपरेटर द्वारा 500 की जगह 750 का प्रोडक्शन देने पर उसे चार घन्टे का ओवर टाइम दिया जाता था।

खींचा-तान में मैनेजमेंट ने एक वैन्डिंग आपरेटर को डिसमिस कर दिया और जनरल आपरेटर को उसके स्थान पर लगा दिया तथा दो इनक्रीमेंट के बदले उसे 750 पीस देने को कहा गया।

वरकर जब इनक्रीमेंट लैटर लेने गया तब मैनेजमेंट ने उसमें निर्धारित प्रोडक्शन 875 पीस लिख दिया। वरकर ने लैटर लेने से इनकार कर दिया। इस पर एग्ज्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजर और परसनल मैनेजर ने 825 लिख कर उनकी बात रखने के लिये लैटर ले लेने और प्रोडक्शन जितना हो उतना करने को कहा। यह अगस्त 92 की बातें हैं।

लैटर ले कर वह वरकर 750 पीस देने लगा और यह सिलसिला डेढ़ साल चला। इस साल मार्च में परसनल मैनेजर ने उस वरकर को बुला कर उसे 825 का निर्धारित प्रोडक्शन देने को कहा। और 23 अप्रैल को उस वरकर को मैनेजमेंट ने कारण बताओ नोटिस दे कर 24 घन्टों में 825 का निर्धारित प्रोडक्शन न दे कर कम्पनी को भारी नुकसान करने के आरोप का उत्तर देने को कहा।

फरीदाबाद में

★ **भारतीया इलेक्ट्रिक स्टील** के मजदूरों को 1980-81 में मैनेजमेंट के खिलाफ तीखे संघर्ष का अनुभव है। बुढिया नाला पर स्थित इस फैक्ट्री में मैनेजमेंट ने दिसम्बर 93 में प्रोडक्शन बन्द कर दिया और वरकरों को तीन महीने फैक्ट्री के अन्दर बैठा कर पहली अप्रैल से 15 दिन की ले आफ कह कर मजदूरों को गेट बाहर कर दिया। 15 अप्रैल को मैनेजमेंट ने नोटिस टाँग कर ले ऑफ 30 अप्रैल तक बढ़ा दी। मैनेजमेंट एक ही सौँस में क्लोजर और अधिकतर मजदूरों की छँटनी की बातें कर रही है। लेकिन काफी-कुछ भुगतने 250 वरकर आजकल फैक्ट्री की दीवार के बाहर तीन-चार टोलियों में हाथ-पर-हाथ धरे बैठे देखे गये हैं — वे कहते हैं कि चन्दीगढ़ में साहबों को आवेदन-निवेदन करने गये लीडरों का इन्तजार कर रहे हैं। वैसे, सड़क से नजर मारने पर भी फैक्ट्री में नया कन्स्ट्रक्शन नजर आता है।

★ **ई एस आई** की डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में इलाज के लिये जाते वरकरों को वहाँ नई और घातक बीमारियाँ वॉनस में देने की स्थितियाँ बदस्तूर जारी हैं। एड्स के केस फरीदाबाद में भी सामने आने के बाद भी ई एस आई में इंजेक्शन देने के लिये डिस्पोजेबल सीरिंग इस्तेमाल नहीं किये जा रहे। ऐसा खर्च कम रखने के लिये किया जा रहा है। मजदूरों के सोचे-विचारे सामुहिक कदम ही ई एस आई को महामारियों के फैलाव का एक और अड्डा बनने से रोक सकेंगे।

★ **ईस्ट इंडिया कॉटन मिल** ने पार्क के लिये जगह को अपने कवाड़ के लिये एक गोदाम बना दिया है।

★ **आटोपिन** मैनेजमेंट ने आधी सड़क को अपने गोदाम में बदल दिया है।

★ **बाटा फैक्ट्री** गेट पर 25 अप्रैल से प्रस्तावित भूख हड़ताल ऐन मौके पर स्थगित।

★ 19 मई को सुबह 10 बजे, 20 को शाम 5 बजे और 21 मई को रात 8 बजे इस अखबार के मई अंक पर मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी में चर्चा होगी। हर कोई इसमें भाग ले सकते हैं।

अगर 150 मजदूर हर महीने दस-दस रुपये दें तो हम इस अखबार की पाँच हजार की जगह दस हजार प्रतियाँ छाप सकेंगे।